हिन्दी मासिक समाचार पत्र PRGI.No-UPHIN/2020/89730

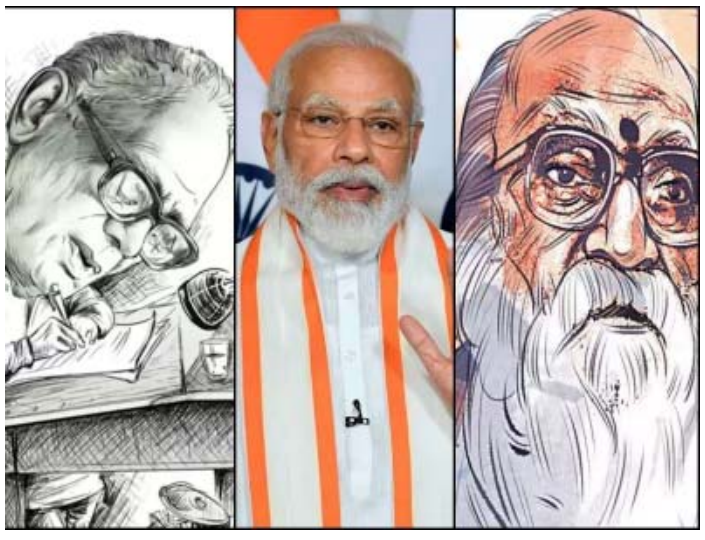
समय मंत्र

www.samaymantra.blogspot.com सिद्धार्थ नगर से प्रकाशित Email- samaymantra55@gmail.com

वर्ष–06 अंक – 12 दिन सोमवार 12 अक्टूबर 2026 पृष्ठ– 8 मूल्य–02 रू0

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, ग्रामीण विकास में उनके योगदान को किया याद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण, ग्रामीण विकास और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने नानाजी देशमुख को एक उत्कृष्ट राष्ट्र–निर्माता बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से यह साबित किया कि वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत जमीनी स्तर से होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नानाजी देशमुख ने राजनीतिक संकल्प को रचनात्मक सामाजिक कार्यों से जोड़कर समाज के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने अपना जीवन ग्रामीण विकास और सामुदायिक भागीदारी को समर्पित कर दिया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि समाज के निचले



स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करके स्थायी और व्यापक बदलाव लाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नानाजी देशमुख ने एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। उनके इस सपने को साकार करने के लिए देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में लिखा, नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि। उन्हें एक उत्कृष्ट राष्ट्र–निर्माता के रूप में आदरपूर्वक याद किया जाता है, जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से यह साबित किया कि वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत जमीनी स्तर से होती है। उनका जीवन राजनीतिक संकल्प और रचनात्मक सामाजिक कार्यों का एक अनूठा संगम था और उन्होंने स्वयं को ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक भागीदारी के लिए समर्पित कर दिया। एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के उनके सपने को साकार करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

प्रधानमंत्री का यह संदेश ग्रामीण विकास, सामाजिक सहभागिता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नानाजी देशमुख के विचारों और योगदान के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की, देशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ पर पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की। उन्होंने मां शैलपुत्री से प्रार्थना की कि उनकी दिव्य कृपा से सभी देशवासियों के हृदय में धैर्य और आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो तथा सब पर माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देवी मां को समर्पित एक भक्ति स्तुति भी साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में लिखा, नवरात्रि के शुभारंभ पर शांति की अधिष्ठात्री मां शैलपुत्री के चरणों में कोटिशरू नमन। उनकी दिव्य कृपा से सभी के मन में धैर्य और आत्मविश्वास का दीप प्रज्वलित हो। देशवासियों पर सदैव मां का आशीर्वाद बना रहे, यही कामना है। प्रधानमंत्री ने मां शैलपुत्री से सभी के जीवन में शांति, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की कामना की। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा–अर्चना के साथ देशभर में नौ दिवसीय पर्व की शुरुआत हुई। दोहराव हटाकर समाचार संक्षिप्त करेंशीर्षक को अधिक समाचारपरक बनाएं

नेपाल में फिर अचानक आई बाढ़: कई पुल और घर बहे, 40 लापता

काठमांडू। नेपाल के गोरखा जिले में रविवार सुबह बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के पानी में अलग–अलग बस्तियों के कम से कम 40 घर बह गए। कई पुल भी नष्ट हो गए हैं। वहीं, कालीगंडकी नदी से जुड़ी एक अन्य घटना में 40 लोगों के लापता होने की खबर है। गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आई बाढ़ के बाद चार लोगों के लापता होने की भी सूचना है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गोरखा जिले की चुमनुबरी ग्रामीण नगरपालिका में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का प्रवाह बाधित हो गया था। इसके बाद नदी में पानी जमा होता रहा। अचानक अवरोध टूटने से पानी तेज गति से आगे बढ़ा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का असर कई बस्तियों में देखने को मिला।

एक अधिकारी के अनुसार, चुमनुबरी ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड छह में उंगिलुंग नदी के किनारे स्थित एक झोपड़ी में रहने वाले चार लोग बाढ़ के बाद से लापता हैं। हालांकि, बूढ़ी गंडकी नदी में आई बाढ़ से अब तक किसी की मौत होने की सूचना नहीं है। बाढ़ रविवार सुबह करीब चार बजे आई। इसके तेज बहाव में बूढ़ी गंडकी जलविद्युत परियोजना का निर्माण शिविर और वहां रखी कई मशीनें भी बह गईं। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक, पायून, जगत, बागर, सल्लेरी और घट्टीखोला सहित कई बस्तियों में घरों को नुकसान पहुंचा है। सिरदिबास और धारचे ग्रामीण नगरपालिकाओं में भी कई मकान प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था को भी भारी क्षति पहुंची है। न्याकचेत और सिरदिबास को जोड़ने वाला पुराना पैदल पुल तथा न्याकचेत और फिलिम बाजार के बीच बना पुल बह गया।

रियाद हवाई अड्डे पर हमले से भड़के ट्रंप, बोले– जल्द पता चलेगा अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी

एजेंसी

वॉशिंगटन। सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए जानलेवा हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को बेहद भयावह और दुखद बताते हुए संकेत दिया कि अमेरिका जल्द ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट कर सकता है। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 309 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है।

संयुक्त बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत भयानक है। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका इस हमले के जवाब में क्या कदम उठाएगा, तो उन्होंने कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यह बहुत भयानक घटना है।

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जो हुआ है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब की रक्षा क्षमता के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी अपनी रक्षा करने में सक्षम है और वहां के सैनिक अच्छे लड़ाके हैं। हालांकि, उन्होंने हवाई अड्डे पर हुए हमले को बेहद गंभीर और दुखद बताया।

हूती विद्रोहियों के साथ अमेरिका के संपर्क को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन की हूती समूहों के साथ बातचीत चल रही है और आगे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि उसे हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होना चाहिए या नहीं। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, संभव है। हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि, सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब तक हमले के लिए किसी संगठन को आधिकारिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया है। दूसरी ओर, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के अधिकारियों और एक राजनयिक सूत्र ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमले का आरोप लगाया है। हूती समूह ने इसी सप्ताह हवाई अड्डे पर हुए पहले के हमलों की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन शनिवार की घटना को लेकर तत्काल कोई दावा नहीं किया।

सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, मृतकों में चार सऊदी नागरिक, दो बांग्लादेशी नागरिक और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक–एक नागरिक शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मृतकों में किसी भारतीय नागरिक का नाम नहीं है। घायलों में कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई गई है। हमले के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों को हवाई अड्डे से दूर रहने की सलाह दी है। उड़ानों के रद्द होने से अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। ईरान से जुड़े सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल पीछे हट सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भविष्य में ईरान के पास परमाणु हथियार न हों। उन्होंने कहा कि स्थिति कुछ शांत होती दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव से पहले ईरान कुछ अतिरिक्त कदम उठा सकता है, यह सोचकर कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस स्थिति को बहुत जल्दी समाप्त कर सकता है। रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका की संभावित प्रतिक्रिया, हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और क्षेत्र में ईरान की भूमिका को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन की ओर से हमले के जवाब में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अभी कोई विस्तृत आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सम्पादकीय

भू–राजनीतिक दबाव

उचित ही इसे असहज करने वाली रवायत का हिस्सा बताया गया है, जिसमें भारत विश्व मंचों पर आतंकवाद विरोधी मुहिम चलाता है, लेकिन भू–राजनीतिक दबाव में हाथ आए संदिग्ध आतंकवादियों को अपने यहां से जाने देता है। म्यांमार से मणिपुर में घुस कर उग्रवादियों ने चार नगा नागरिकों की हत्या कर दी। इस घटना से मणिपुर में जारी हिंसा के साथ सीमा पार का पहलू जुड़े होने की फिर पुष्टि हुई है। ये वारदात उस समय हुई, जब अमेरिकी एजेंट मैथ्यू वॉनडाइक और छह यूक्रेनी ड्रोन विशेषज्ञों को भारत से बाहर जाने देने की इजाजत मिल गई है। इन सभी को इस वर्ष मार्च में संदिग्ध स्थितियों में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि ये सभी मणिपुर के रास्ते म्यांमार गए। इस मामले को भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवादी गतिविधियों और विदेशी हस्तक्षेप की शिकायत से जोड़ कर देखा गया। वॉनडाइक अमेरिकी भाड़े का सैनिक है, जो सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नामक विवादास्पद संस्था से जुड़ा है। लीबिया, सीरिया, इराक, और अफगानिस्तान जैसे युद्ध क्षेत्रों में उसकी भूमिका विवादास्पद रही है।

भारत में भी पहले उस पर आतंकवाद से जुड़ी धारा लगाई गई, लेकिन चार्जशीट पेश करते वक्त यूएपीए हटा दिया गया। विपक्ष एवं कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर कड़ा एतराज जताया था। उनका इल्जाम है कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के हस्तक्षेप के कारण भारत सरकार ने इन लोगों पर नरमी बरती। बीते मई मे भारत यात्रा के समय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी ये मामला उठाया था। विश्लेषकों ने उचित ही इस कांड को उस लंबी और असहज करने वाली रवायत का हिस्सा माना है, जिसमें भारत अपने सख्त कानूनों का हवाला तो देता है, और विश्व मंचों पर आतंकवाद विरोधी मुहिम चलाता है, लेकिन भू–राजनीतिक दबाव पड़ते ही हाथ आए संदिग्ध आतंकवादियों को दंडित करने से पीछे हट जाता है। खुद भारतीय अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक वॉनडाइक का गुट बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है, जो तस्करी कर ड्रोन्स भारत लाता था और फिर उन्हें म्यांमार भेजता था। इसके पहले भोपाल गैस लीक कांड में यूनियन कारबाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन, पुरुलिया में हथियार गिराने के आरोपियों, और केरल में भारतीय मछुआरों के हत्यारे इटली के दो नौसैनिकों के प्रति भी ऐसी नरमी बरती गई थी। ये तमाम घटनाएं भारतीय राज्य के सॉफ्ट (कमजोर) बने रहने की दुर्भाग्यपूर्ण मिसाल हैं।

समेकित खेती से संवरी केकराखोली की तस्वीर

धमतरी जिले का मगरलोड विकासखण्ड आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आधुनिक कृषि की एक नई गाथा लिख रहा है। यहाँ के ग्राम पंचायत केकराखोली में श्सेवा संकल्प अभियानश के अंतर्गत शासकीय योजनाओं के समन्वित उपयोग से कृषि के परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आया है। वीबी–जी रामजी और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त अभिसरण से संचालित समेकित फल उद्यान योजना ने गाँव के 25 किसानों की जीवनशैली और खेती के तरीकों को एक नया आयाम दिया है, जिससे लगभग 35 एकड़ भूमि अब लहलहाते फलोद्यानों और बहुफसली कृषि गतिविधियों का केंद्र बन चुकी है।

केकराखोली के इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत भूमि का वैज्ञानिक और रणनीतिक उपयोग है। किसानों ने अपनी जमीन पर केवल पारंपरिक फसलें उगाने के बजाय आम और कटहल जैसे दीर्घकालिक फलदार पौधों के साथ–साथ हल्दी, उड़द, करेला और बरबटी जैसी अल्पकालिक फसलों की अंतरवर्ती (इंटरक्रॉपिंग) खेती शुरू की है। इसके अतिरिक्त सतावर और सिंदूरी जैसे औषधीय पौधों को भी खेतों का हिस्सा बनाया गया है। जब तक फलदार वृक्ष बड़े होकर उत्पादन देना शुरू नहीं करते, तब तक किसान इन छोटी अवधि की फसलों से नियमित आय प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी दैनिक और मौसमी वित्तीय जरूरतें सहजता से पूरी हो रही हैं। खेती को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं था, इसलिए योजना के तहत मजबूत अवसंरचनात्मक ढांचा भी तैयार किया गया। खेतों को आवारा मवेशियों और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सुरक्षित करने के लिए घेराबंदी (फेंसिंग), निर्बाध सिंचाई के लिए बोरवेल और पौधों को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए ग्रीन शेड हाउस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विभागीय संसाधनों के इस एकीकृत समन्वय ने किसानों को एक संरक्षित और आधुनिक कृषि आधार प्रदान किया है। जल संरक्षण और अतिरिक्त आजीविका के उद्देश्य से ग्राम पंचायत में 07 आजीविका डबरियों का निर्माण भी किया गया है। ये डबरियाँ न केवल खेतों की सिंचाई और भू–जल स्तर को बनाए रखने में मददगार साबित हो रही हैं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल इनमें मछली पालन भी किया जा रहा है। इससे किसानों को पारंपरिक खेती के साथ–साथ जल–आधारित आय का एक नया और टिकाऊ विकल्प मिल गया है, जो उनकी कुल आय में इजाफा कर रहा है। केकराखोली का यह एकीकृत कृषि मॉडल आज अल्पकालिक आय, दीर्घकालिक फलदार उत्पादन और मत्स्य पालन जैसी अतिरिक्त आजीविका को एक सूत्र में पिरोकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। 25 किसानों के सामूहिक प्रयास और शासकीय योजनाओं के सफल अभिसरण से विकसित यह 35 एकड़ का क्षेत्र पूरे राज्य के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन चुका है। यह पहल स्पष्ट करती है कि जब किसान की अटूट मेहनत, उपलब्ध संसाधन और सही शासकीय योजनाएं एक साथ मिलती हैं, तो ग्रामीण समृद्धि की एक मजबूत और स्थायी नींव तैयार होती है।

संशोधित ईपीएफ सीमा और सामाजिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण, कदम-दर-कदम आगे बढ़ते हुए

विश्वकर्मा जयंती पर, कामगारों और शिल्पकारों का सम्मान करने वाले इस पर्व के अवसर पर सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के बहुत समय से लंबित निर्णय की घोषणा की। कोई पूछ सकता है कि सीमा में 10,000 रुपये की वृद्धि से आखिर क्या बदलाव आएगा? इस संशोधन की आवश्यकता क्यों है और इसका कर्मचारी या नियोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए, मूल बातों से शुरुआत करते हैं।

25,000 रुपये की यह वैध ाानिक वेतन सीमा अनिवार्य ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा–लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) कवरेज के लिए सीमा का काम करती है। ये तीनों योजनाएं भारत में वेतनभोगी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के मूल आध ाार हैंरू सेवानिवृत्तिध्आपातकालीन निधिय नियोक्ता के अंशदान से वित्तपोषित पेंशन निधि, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान किया जाता हैय और जीवन बीमा, जिसे नियोक्ता के अंशदान से ही वित्तपोषित किया जाता है, जिससे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को सहायता मिल सके। पूर्णतरू उचित यही है कि सामाजिक सुरक्षा को साल 2014 से स्थिर किसी संख्या पर आध ाारित न रखा जाए, जबकि इस अवधि में वेतन, न्यूनतम मजदूरी और जीवन–यापन की लागत लगातार बढ़ती रही है।

पिछली वेतन सीमा के तहत, 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करने वाला कोई भी नया कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफ कवरेज से बाहर हो जाता था, ईपीएस के लिए पात्र नहीं होता था और ईडीएलआई के संरक्षण से भी वंचित रहता था। किसी मौजूदा कर्मचारी का वेतन समय के साथ इस सीमा से अधि ाक हो जाने पर कवरेज समाप्त नहीं होती थी, लेकिन ईपीएस के तहत पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये पर ही सीमित रहता था। कोई यह तर्क दे सकता है कि अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी इसके बजाय स्वैच्छिक कवरेज का विकल्प चुन सकते हैं। इस तर्क में समस्या यह है कि सीमा से अधिक वेतन पर स्वैच्छिक नामांकन के लिए संयुक्त विकल्प के तहत नियोक्ता की सहमति आवश्यक होती है, जिससे यह विकल्प सुनिश्चित अधिकार के बजाय सौदेबाजी का विषय बन जाता है। बढ़ी हुई वेतन सीमा के साथ, यह कवरेज सौदेबाजी का विषय न रहकर अधिकार बन जाएगी।

बढ़ी हुई वेतन सीमा कामगारों से जुड़ी सभी समस्याओं का समाध ाान तो नहीं करती, लेकिन यह औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र को थोड़ा अधिक न्यायसंगत और थोड़ा व्यापक जरूर बनाती है। 10,000 रुपये की वृद्धि भले ही मामूली लगती हो, लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा तंत्र के दायरे में आने वाले अतिरिक्त 51 लाख कामगारों की संख्या मामूली नहीं है। और अधिकांश अधिकारों के विपरीत, इस अधिकार का लाभ लेने के लिए कामगार को अपनी ओर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

मनुष्य अपने भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए तैयारी करने में खास अच्छे नहीं होते। 65 वर्ष की उम्र के अपने भावी स्वरूप के लिए कोई बजट नहीं बनाता। हम अक्सर उस छोटे लाभ को चुनते हैं जो जल्दी मिल जाए, बजाय उस बड़े लाभ के जो देर से मिले। व्यवहार अर्थशास्त्र में इसे श्हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंगच्य कहा जाता है। परिणामस्वरूप, सीमित आय में तत्काल उपभोग की जरूरतों को पूरा करने की तुलना में भविष्य में अपने लिए या किसी भावी परिस्थिति के लिए बचत करना और योजना बनाना अक्सर अधिक कठिन होता है। यही कारण है कि ईपीएफओ द्वारा संचालित अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान जैसी व्यवस्थाओं की रूपरेखा महत्वपूर्ण है। यह बचत के लिए कामगार की इच्छा या इच्छाशक्ति पर निर्भर किए बिना काम करती है। आय के कामगार के खाते में पहुंचने से पहले ही पेंशन के लिए अंशदान अलग रख दिया जाता हैकृजो पैसा कभी दिखाई ही नहीं देता, उसे खर्च करना संभव नहीं होता। और धीरे–धीरे, हर महीने वेतन का एक छोटा हिस्सा अलग रखा जाता है, जिससे सेवानिवृत्ति निधि ा तैयार होती है, जिसका उपयोग आपातकाल में भी किया जा सकता है, साथ ही जीवन बीमा का कवरेज भी मिलता हैकृवह भी आपके अपनी ओर से बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए।

हालांकि, इस संशोधन के साथ नियोक्ताओं के लिए एक लागत भी जुड़ी हुई है। अनिवार्य वेतन सीमा अब बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने के साथ, नियोक्ताओं को काफी अधिक संख्या में कर्मचारियों को वैध ाानिक ईपीएफ कवरेज प्रदान करनी होगी और उनके मासिक अंशदान संबंधी दायित्व भी बढ़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, 22,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला ऐसा कर्मचारी, जो पहले अनिवार्य कवरेज से बाहर था, अब वैधानिक रूप से ईपीएफ कवरेज के दायरे में आएगा और नियोक्ता के लिए इस कर्मचारी को ईपीएफ कवरेज प्रदान करना अनिवार्य होगा। अब नियोक्ता को वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान करना होगा, जो ईपीएस पेंशन योजना और कर्मचारी के अपने ईपीएफ खाते के बीच विभाजित होगा। यह राशि प्रति कर्मचारी प्रति माह 2,640 रुपये या वार्षिक 31,680 रुपये होगी। ऐसे 20 कर्मचारियों के मामले में, यह अतिरिक्त पेरोल लागत के रूप में प्रति वर्ष 6,33,600 रुपये होगी। इसके अलावा, ईडीएलआई बीमा अंशदान भी होगा, जो राशि में भले ही छोटा है, लेकिन अब इसकी गणना भी अधिक वेतन आधार पर की जाएगी। नियुक्ति संबंधी निर्णय लेते समय यह नियोक्ताओं के लिए एक वास्तविक लागत है।

अधिक लागत कंपनी के लिए एक स्पष्ट निष्कर्ष प्रतीत होती है, लेकिन यह केवल प्रारंभिक प्रभाव है और रोजगार बाजार इससे कहीं अधिक जटिल है। अधिक ईपीएफ कवरेज भर्ती के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में काम करता है, जिससे अधिक कुशल और अधिक कार्य–क्षमता वाले कामगार आकर्षित होते हैं, क्योंकि नए कर्मचारी किसी नौकरी का मूल्यांकन करते समय केवल मासिक वेतन को ही ध्यान में नहीं रखते। यह कवरेज कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने में भी सहायक हो सकती है। पेंशन और बीमा लाभ वाला कामगार संभवतरू अधिक समय तक काम पर बना रहेगा और नौकरी की शुरुआत थोड़ी अधिक सुरक्षा के साथ करेगा। दूरदर्शी नियोक्ता पहले से ही इसे समझते हैं और अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए स्वैच्छिक कवरेज प्रदान करते हैं।

सामाजिक सुरक्षा की अवध ाारणा यह है कि यह ट्रैम्पोलीन की तरह न केवल आपको संभालती है, बल्कि फिर से उछलकर आगे बढ़ने में भी सक्षम बनाती है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य कामगारों को ऐसा कोष उपलब्धकराना है, जिससे वे आपातकाल के समय या सेवानिवृत्ति के बाद आवश्यकता पड़ने पर धन प्राप्त कर सकें, जिससे कोई अस्थायी संकट जीवनभर की कठिनाई का रूप न ले और उन्हें ऋण–जाल में न फंसाए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी पहलें, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अधि ाक किफायती और सुलभ बनाया है, इस सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाती हैं। बदलते रोजगार स्व रूप हेतु तैयारी करने के लिए मजबूत उद्योग संपर्कों के साथ, कौशल उन्नयन, पुनरूकौशल विकास और नव कौशल विकास के लिए कौशल विकास पारितंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अंशदायी पेंशन कवरेज को उन लोगों के लिए कम आय वर्ग तक और आगे बढ़ाती है, जो निवेश जोखिम उठाने और आर्थिक तथा बाजार वृद्धि के लाभों में भागीदारी के इच्छुक हैं। यह ट्रैम्पोलीन भी कदम दर कदम मजबूत होता जा रहा है।

आमकोल/छबैला की चौपाल में गूंजा स्थानीय नेतृत्व का संकल्प

गोरखपुर/चौरीचौरा। विधानसभा चौरीचौरा के सरदारनगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा आमकोल एवं छबैला में



जनप्रिय नेता मां तरकुलहा देवी के अनन्य भक्त तथा अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की गौरवशाली विरासत के वाहक अजय कुमार सिंह 'टप्पू भैया' के नेतृत्व में विशाल चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पंडित राजकुमार व्यास ने किया। चौपाल में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत बनाने, क्षेत्रीय विकास और जनसमस्याओं के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने टप्पू भैया के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए उन्हें विधायक बनाने का भरोसा जताया। चौपाल को संबोधित करते हुए टप्पू सिंह ने कहा कि यदि जनता उन्हें चौरीचौरा का विधायक बनने का अवसर देती है, तो क्षेत्र में व्याप्त बिचौलियागिरी और थाना–तहसील की दलाली पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में जनता के सुख–दुःख में सहभागी बनना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर तत्पर रहना है।

उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचने वाले कई जनप्रतिनिधि चुनाव समाप्त होने के बाद क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। इससे जनता और जनप्रतिनिधि के बीच दूरी बढ़ती है तथा स्थानीय समस्याएं उपेक्षित रह जाती हैं। चौरी–चौरा को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जो केवल चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल में जनता के बीच रहकर उसकी आवाज उठाए। टप्पू सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान लोग अलग–अलग राजनीतिक दलों में बंट जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सभी चौरी–चौरा के निवासी हैं। क्षेत्र की एकता, सम्मान और विकास के लिए स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना आवश्यक है। केंद्र और प्रदेश सरकारों की अपनी भूमिका है, लेकिन क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना स्थानीय जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चौरीचौरा की जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दर–दर भटकने को मजबूर नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर चंद्रदेव उपाध्याय, नरेंद्र ओझा, दाढ़ी बाबा, महेंद्र ओझा, मुनेश्वर विश्वकर्मा, अनिल उपाध्याय, केसरी ओझा, संतोष दुबे, शिबू सिंह, भास्कर शर्मा, धनंजय सिंह उपाध्याय, रामाज्ञा भारती, घनश्याम पांडेय, पवन ओझा, रामवत उपाध्याय, छेदी गुप्ता, सुन्नी नेता, सुग्रीव भारती, गौरी शंकर दुबे, अरविंद उपाध्याय, महंत विश्वकर्मा, राजकुमार यादव, विनोद यादव, विजय यादव, रामानंद यादव, गोलू ओझा, अजय निषाद, चंद्रभूषण ओझा, रामदयाल शुक्ला, राजेशमल, सुरजनाथ यादव, रामदौड़ प्रजापति, छेदिमल, लालजी प्रसाद, सदर अली, लाल बहादुर निषाद, चंद्रभान माल, कोमल चौहान, अशोक चौधरी, सुनील माल, सुभाष चौधरी, अशफाक अहमद, जय हिंद चौधरी, रामचंद्र प्रसाद, नर्मदा माल, योगेंद्र सिंह और राजकुमार भारती सहित अनेक गणमान्य नागरिक, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मासिक बैठक में पत्रकारों ने रखे अपने विचार

पत्रकार संगठन की मजबूती पर दिया गया जोर।



शोहरतगढ/सिद्धार्थनगर। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मासिक बैठक रविवार को आयोजित की गयी। बैठक में संगठन से जुड़े पत्रकारों ने प्रतिभाग किया और अपने–अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किये और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं, पत्रकारों के हितों और संगठन की भूमिका जैसे विषयों पर अपना पक्ष रखा। सभी ने विभिन्न मुद्दों पर आपसी विचार–विमर्श किया और पत्रकारों के बीच एकजुटता बनाये रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के दौरान पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, अधिकारों तथा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार समाज की समस्याओं को सामने लाने और आमजन की आवाज जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। पत्रकारों ने अपने सुझाव रखते हुए संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने पर विचार व्यक्त किये। बैठक का उद्देश्य आपसी संवाद के माध्यम से पत्रकारों की समस्याओं को समझना तथा उनके समाधान के लिए मिलकर प्रयास करना रहा। अन्त में सभी पत्रकारों ने आपसी सहयोग, एकता और संगठनात्मक मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकाई शोहरतगढ़ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति रहीं।

मां तरकुलहा देवी धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब



गोरखपुर। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर रविवार को पूर्वांचल के प्रमुख शक्तिपीठ मां तरकुलहा देवी धाम में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तीन बजे से ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। सुबह होते–होते मंदिर परिसर में लंबी कतारें लग गईं। मां के जयकारों के बीच श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए दर्शन–पूजन करते नजर आए। नवरात्र को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास की दुकानों पर विशेष रौनक रही। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया था। फूल, प्रसाद, नारियल और चुनरी की दुकानें श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। सुबह से ही पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही जारी रही। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जगह–जगह पुलिसकर्मी सक्रिय नजर आए। मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने और दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन कराने के लिए निगरानी की जाती रही। मंदिर प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से बार–बार उद्घोषणा कर श्रद्धालुओं को अपने सामान की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई। दोपहर एक बजे तक मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिली। ट्रस्ट के महामंत्री राजेश जायसवाल ने बताया कि दोपहर बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी आने की संभावना है, जबकि शाम को दर्शनार्थियों की भीड़ फिर बढ़ सकती है। नवरात्र महापर्व के अवसर पर धाम में दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। सुबह–शाम होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचकर मां तरकुलहा देवी की पूजा–अर्चना कर सुख–समृद्धि और कल्याण की कामना कर रहे हैं।

पचदेवरी में निकली भव्य कलश यात्रा

गोरखपुर। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन झंगहा थाना क्षेत्र के पचदेउरी गांव में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा निवेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर विधि–विधान से पवित्र जल भरा। कलश यात्रा के दौरान मां दुर्गा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। नवरात्रि के शुभारंभ पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं ने धार्मिक आस्था और भक्ति का परिचय दिया। गांव में नवरात्रि पर्व को लेकर उत्साह का माहौल रहा। कलश यात्रा के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नई बाजार चौकी इंचार्ज ए.के. सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान नीलू दुबे, अम्बुज तिवारी, कृष्णा दुबे, सुनील यादव उर्फ बुल्लु, नकुल, रमेश, कपिल, बृजेश और रमाशंकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की कलश स्थापना



गोरखपुर। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर रविवार को पूर्वांचल के प्रमुख शक्तिपीठ मां तरकुलहा देवी धाम में नौ दिवसीय नवरात्र महापर्व का शुभारंभ विधिवत पूजा–अर्चना एवं कलश स्थापना के साथ हुआ। मां तरकुलहा देवी धाम चौरिटेबल ट्रस्ट एवं व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में चौरीचौरा के विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की। पंडित गिरजा शंकर मिश्रा एवं पंडित आनंद मिश्रा ने विधि–विधान से पूजा–पाठ संपन्न कराया। इस दौरान वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। नवरात्र के नौ दिनों तक मंदिर में प्रतिदिन सुबह–शाम मां दुर्गा की आराधना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित गिरजा शंकर मिश्रा एवं पंडित विष्णु तिवारी के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। शाम को भजन–कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट एवं व्यापार मंडल की ओर से प्रतिदिन दोपहर में प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। प्रथम दिन विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने दोपहर 12 बजे श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट एवं व्यापार मंडल की ओर से मंदिर के मुख्य गेट से गोरखपुर–देवरिया मार्ग तक निशुल्क ऑटो रिक्शा सेवा की शुरुआत भी की गई। इस अवसर पर ऑटो चालकों को अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया और वाहनों को मंदिर के मुख्य द्वार से रवाना किया गया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के महामंत्री राजेश जायसवाल, नरेंद्र पांडेय, डॉ. दिनेश यदुवंशी, अमरनाथ जायसवाल, ऋषि साहनी, हिमाचल साहनी, उज्ज्वल साहनी, अमरजीत पासवान विजय जायसवाल धर्मेंद्र जायसवाल आनंद मिश्रा, सोनू पासवान, संतोष गुप्ता, हरीश राजभर, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार गुप्ता, अमित जायसवाल एवं मंडल अध्यक्ष तारकेश्वर जायसवाल सहित अनेक श्रद्धालु एवं व्यापारी उपस्थित रहे। नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक आयोजनों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए ट्रस्ट एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी सक्रिय रहेंगे।

नारी शक्ति सम्मान' कार्यक्रम में महिला पुलिस हुई सम्मानित



गोरखपुर। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर 'नवरात्रि नारी शक्ति सम्मान एवं कन्या पूजन कार्यक्रम–2026' के अंतर्गत झंगहा थाने में महिला सुरक्षा, कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा के प्रति समर्पित महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में झंगहा थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर महिला पुलिसकर्मी नेहा पटेल, प्रतिभा रावत, साक्षी तिवारी, निधि राजभर, कंचन कुमारी, रोशनी यादव, रजनी, निधि सिंह, प्रतिज्ञा सिंह, सुप्रिया सिंह, रंजना कुमारी, वैशाली शर्मा, पुष्पा एवं लक्ष्मी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक एवं समाजसेवी पंडित एस. के. शर्मा ने कहा कि नवरात्रि केवल माँ दुर्गा की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का भी अवसर है। महिला पुलिसकर्मी अपने साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भाव से समाज में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके योगदान का सम्मान करना हम सभी का सामाजिक दायित्व है। एस. के. शर्मा जी ने कहा, "नारी का सम्मान, समाज का सम्मान है। हमारी मातृशक्ति और महिला सुरक्षा कर्मियों का समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

मेरा प्रयास है कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हो और जनसेवा के क्षेत्र में समर्पित महिलाओं को उचित मान–सम्मान मिले। सेवा, सम्मान और सामाजिक समरसता के इस संकल्प को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने नंदौर में नई पुलिस चौकी का किया उद्घाटन

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने किया उद्घाटन, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी, नियमित गश्त और वाहन चेकिंग के दिए निर्देश

संतकबीरनगर। जिले के थाना बखिरा क्षेत्र में कानून–व्यवस्था मजबूत करने और स्थानीय लोगों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवनिर्मित नंदौर पुलिस चौकी का रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने फीता काटकर और विधिवत पूजन–अर्चन के साथ चौकी का शुभारंभ किया। पुलिस विभाग को उम्मीद है कि इस चौकी के संचालन से नंदौर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बढ़ेगी तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

उद्घाटन के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों, अवैध तस्करी और आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित गश्त, सघन वाहन चेकिंग और जरूरत के अनुसार पुलिस की सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही, चौकी पर आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत संवेदनशीलता से सुनने और उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

चौकी खुलने से क्या बदलेगा?

किसी क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच दूरी कम करना, आपात स्थिति में सहायता की उपलब्धता बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर कानून–व्यवस्था की निगरानी मजबूत करना होता है। नंदौर में नई चौकी शुरू होने से स्थानीय नागरिकों को अपनी शिकायत लेकर पुलिस तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पुलिस की नियमित मौजूदगी महत्वपूर्ण होती है, जहां लोगों को शिकायत दर्ज कराने या तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए दूर स्थित थाने तक जाना पड़ता है। हालांकि, चौकी का उद्घाटन अपने आप में अपराध नियंत्रण की गारंटी नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती है या नहीं, चौकी कितने समय सक्रिय रहती है और शिकायतों पर कितनी तत्परता से कार्रवाई होती है।

अपराध नियंत्रण के लिए केवल निर्देश नहीं, नियमित निगरानी भी जरूरी

पुलिस अधीक्षक ने नंदौर और आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों तथा अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बल को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। आपात स्थिति में स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

इन निर्देशों का असर तभी दिखाई देगा, जब नियमित गश्त और वाहन चेकिंग लगातार प्रभावी ढंग से संचालित हों। साथ ही, पुलिस को स्थानीय लोगों से संवाद बनाए रखना होगा, ताकि क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों और संभावित अपराधों की जानकारी समय रहते मिल सके। पुलिस की जवाबदेही और जनता का सहयोग, दोनों ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनसुनवाई की गुणवत्ता भी होगी अहम कसौटी

पुलिस चौकी का एक महत्वपूर्ण दायित्व पीड़ितों की शिकायत सुनना और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा देना है। पुलिस अधीक्षक ने भी चौकी पर आने वाले प्रत्येक पीड़ित की समस्या संवेदनशीलता से सुनने और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

लेकिन आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि क्या उनकी शिकायतों पर समय से कार्रवाई होगी? क्या छोटे विवादों से लेकर गंभीर मामलों तक पुलिस निष्पक्षता से सुनवाई करेगी? और क्या पीड़ितों को बार–बार अधिकारियों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी?

नवरात्रि-दशहरा को लेकर पुलिस अलर्ट, महुली और दुधारा में ग्राम प्रहरियों के साथ बैठकय संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश'

मूर्ति विसर्जन और दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा पर जोर, गांवों में विवाद या अशांति की आशंका होने पर तत्काल सूचना देने को कहा गया

संतकबीरनगर। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और मूर्ति विसर्जन के दौरान शांति एवं कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए संतकबीरनगर पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने की कवायद शुरू की है। इसी क्रम में 11 अक्टूबर 2026 को थाना महुली और थाना दुधारा परिसर में ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) के साथ बैठकें आयोजित की गईं। दोनों बैठकों में गांवों के दुर्गा प्रतिमा पंडालों, प्रमुख आयोजन स्थलों और संवेदनशील गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए।





पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में थाना महुली की बैठक थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई, जबकि थाना दुधारा में थानाध्यक्ष अमित कुमार कुशवाहा ने ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

गांवों में सतर्कता और पुलिस से तत्काल समन्वय पर जोर

बैठकों में ग्राम प्रहरियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने–अपने गांवों में स्थापित दुर्गा प्रतिमा पंडालों और प्रमुख आयोजन स्थलों पर सतर्क निगरानी रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, आपसी विवाद या शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका सामने आने पर तत्काल संबंधित थानाध्यक्ष, बीट पुलिस अधिकारी अथवा हल्का प्रभारी को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। ग्राम प्रहरियों से असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत बनाने और पुलिस व ग्राम प्रहरियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

थाना महुली में बैठक के दौरान ग्राम प्रहरियों को फल वितरित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इसे ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका और योगदान के प्रति सम्मान के रूप में देखा गया।

त्योहारों की सुरक्षा में ग्राम प्रहरियों की भूमिका अहम

ग्रामीण इलाकों में ग्राम प्रहरी स्थानीय गतिविधियों और संभावित विवादों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुर्गा पूजा पंडालों, जुलूसों और मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ बढ़ने तथा अलग–अलग आयोजनों के एक साथ होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर सतर्कता और समय पर सूचना का विशेष महत्व रहता है।

हालांकि, केवल बैठक और निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्राप्त सूचनाओं पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है, संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी कैसी रहती है और किसी विवाद की स्थिति में संबंधित अधिकारी कितनी तत्परता से हस्तक्षेप करते हैं।

असली कसौटीरू निर्देशों का जमीन पर पालन

महुली और दुधारा में हुई बैठकों से त्योहारों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी और समन्वय मजबूत करने का प्रयास सामने आया है। अब जरूरी होगा कि ग्राम प्रहरियों को स्पष्ट सूचना–प्रणाली उपलब्ध रहे और उनकी ओर से दी गई शिकायतों या चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए।

त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी पुलिस, प्रशासन, आयोजन समितियों और स्थानीय नागरिकों की साझा है। सतर्कता के साथ संवाद, समय पर कार्रवाई और आपसी सहयोग ही किसी संभावित विवाद को बढ़ने से रोकने में मददगार हो सकते हैं।

मिशन संदेश की नजररू त्योहारों से पहले पुलिस की तैयारियां जरूरी हैं, लेकिन उनकी सफलता का आकलन बैठकों की संख्या से नहीं, बल्कि गांवों में शांति, सुरक्षा और समय पर पुलिस कार्रवाई से होगा।

बेलहरकला थाने को मिला आधुनिक भवन, अब अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय की होगी असली परीक्षा“

मुख्यमंत्री ने अगस्त में किया था भवन का लोकार्पण, नवरात्रि के पहले दिन विधायक अनिल त्रिपाठी और एसपी संदीप कुमार मीना की मौजूदगी में पूजन के बाद शुरू हुआ नए परिसर से कामकाज



संतकबीरनगर। जिले के बेलहरकला थाने को आखिरकार चौकी सांथा से नवनिर्मित थाना भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना की मौजूदगी में नए भवन का विधि–विधान से पूजन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर थाना परिसर में पौधरोपण भी किया गया।

नया थाना भवन आधुनिक सुविधाओं और बेहतर आधारभूत संरचना के साथ तैयार किया गया है। इसमें पुलिसकर्मियों के लिए बैरक, कार्यालय, प्रशासनिक भवन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था होने की बात कही गई है। प्रशासन का मानना है कि इससे पुलिसकर्मियों को कामकाज के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा और क्षेत्र के लोगों को पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

हालांकि, किसी थाने की प्रभावशीलता केवल उसके भवन, कार्यालयों और सुविधाओं से नहीं मापी जा सकती। असली कसौटी यह होगी कि नए परिसर में स्थानांतरण के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में कितना सुधार आता है और आम नागरिकों को इसका कितना प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।

अगस्त में हुआ था लोकार्पण, अब शुरू हुआ नए भवन से संचालन

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, नवनिर्मित थाना भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अगस्त 2026 को किया था। इसके करीब दो महीने बाद 11 अक्टूबर को पूजन के उपरांत थाने को नए भवन में स्थानांतरित किया गया। इस क्रम से यह सवाल भी उठता है कि लोकार्पण और नियमित संचालन के बीच की अवधि में किन औपचारिकताओं अथवा व्यवस्थागत तैयारियों को पूरा किया गया। हालांकि, इस देरी के कारणों को लेकर उपलब्ध सूचना में कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

बड़े क्षेत्रफल वाले थाने के सामने बड़ी जिम्मेदारी

बेलहरकला थाने को प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा थाना बताया गया है। यदि इसका भौगोलिक दायरा व्यापक है, तो पुलिस के सामने गश्त, घटनास्थल तक समय से पहुंचने, दूरस्थ गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई जैसी चुनौतियां भी महत्वपूर्ण होंगी।

ऐसे में नए भवन के साथ पुलिस बल की पर्याप्त उपलब्धता, संसाधनों का सही उपयोग, नियमित क्षेत्र भ्रमण और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। केवल आधुनिक परिसर तैयार हो जाने से दूर–दराज के गांवों तक पुलिस की पहुंच अपने आप बेहतर नहीं हो जाती।

जनता को क्या मिलेगा लाभ?

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और क्षेत्र में शांति व कानून–व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। नए भवन से पुलिसकर्मियों को कामकाज में सुविधा मिलने की उम्मीद है, लेकिन नागरिकों के लिए इसकी उपयोगिता तभी साबित होगी, जब शिकायत दर्ज कराने, सुनवाई, विवेचना और आवश्यक पुलिस सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सहज और प्रभावी बने।

इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैंकृक्या थाने में पर्याप्त पुलिसकर्मी और जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं? क्या शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध कार्रवाई की जानकारी मिलेगी? क्या क्षेत्र के दूरस्थ गांवों में पुलिस की नियमित मौजूदगी बढ़ेगी? और क्या नए भवन के साथ जनसुनवाई की गुणवत्ता में भी सुधार दिखाई देगा?

इन सवालों के जवाब आने वाले समय में थाने की कार्यप्रणाली से सामने आएंगे। फिलहाल, नए भवन में स्थानांतरण पुलिस व्यवस्था के लिए एक आधारभूत बदलाव हैय इसकी वास्तविक सफलता जनता की सुरक्षा, शिकायतों के निस्तारण और पुलिस के प्रति भरोसे में होने वाले सुधार से तय होगी।

अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी धनघटा अभय नाथ मिश्रा, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रामबली यादव और थानाध्यक्ष बेलहरकला सर्वेश कुमार सहित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।





नवजात की कथित गला दबाकर हत्या का मामला, पुलिस ने वांछित अभियुक्तको किया गिरफ्तार

मासूम की मौत से उठे गंभीर सवाल, दुधारा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय भेजा

संतकबीरनगर। जिस नवजात ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी, उसकी कथित गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आने से क्षेत्र में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। थाना दुधारा क्षेत्र में दर्ज इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद वांछित अभियुक्त रामअवध को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों का खुलासा न्यायिक जांच एवं विवेचना के दौरान ही स्पष्ट हो सकेगा।

पुलिस के अनुसार, डिघवा निवासी रामअवध पुत्र इसरी के खिलाफ नवजात की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने 10 अक्टूबर 2026 को थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र दिया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 408/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 352, 351(3) और 333 में मामला दर्ज किया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को दुधारा पुलिस ने रामअवध को डिघवा से मठिया जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रवाना किया गया।

मासूम की मौत, कई सवालों के जवाब तलाशना जरूरी

नवजात की मौत से जुड़ा यह मामला केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घटना की परिस्थितियों और कथित अपराध के पीछे की वजहों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता भी सामने लाता है। आखिर ऐसी कौन–सी परिस्थितियां बनीं, जिनमें एक नवजात की जान चली गई? घटना के समय क्या हुआ था और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि किन साक्ष्यों से होती है? इन सवालों का जवाब पुलिस की निष्पक्ष विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया से सामने आना महत्वपूर्ण है।

एक नवजात अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह बड़ों पर निर्भर होता है। ऐसे में उसकी मौत से जुड़ी किसी भी घटना की जांच संवेदनशीलता, निष्पक्षता और साक्ष्यों के आधार पर किया जाना जरूरी है। साथ ही, आरोपों को न्यायालय में प्रमाणित होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्रवाई

पुलिस विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में की गई।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अमित कुशवाहा, उपनिरीक्षक प्रमोद सिंह, कांस्टेबल रंजन कुमार, कांस्टेबल आदर्श श्रीवास्तव और महिला कांस्टेबल एकता सिंह शामिल रहीं।

गिरफ्तारी के बाद अब विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया पर नजर

आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस की कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों का संकलन, आरोपों की पुष्टि और निष्पक्ष विवेचना आवश्यक है। नवजात की मौत के मामले में परिजनों को न्याय मिलना और घटना की वास्तविक परिस्थितियां सामने आना सबसे महत्वपूर्ण है।

मासूम की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद मिल सकती है।

अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि विवेचना में कौन–से तथ्य सामने आते हैं

और न्यायालय में मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।

पर्यटन के जरिए ग्रामीण सशक्तिकरणः विष्णु देव साय सरकार की अनूठी पहल

नया छत्तीसगढ़, नई उम्मीदें: पर्यटन से गांवों की तस्वीर बदलने वाले नायकों की अनकही कहानी

छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण तक नैसर्गिक विरासत की अमूल्य धरा है, जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और जनजातीय परंपराएं छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक विविधता से परिचित कराना है।

छत्तीसगढ़ का बस्तर, पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान, संस्कृति और प्रकृति की अनुपम छटा वाले पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। वास्तव में बस्तर का वन क्षेत्र बेहद निराला है। प्रकृति की हरियाली और स्वच्छता पर्यटकों को आकर्षित करता है। धीरे–धीरे बस्तर न केवल विकास की धारा से जुड़ रहा है बल्कि पयर्टन के हिसाब से भी तेजी से बदल रहा है। यहां का खूबसूरत इलाका अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों की छटा सबका ध्यान खींच रहा है। साथ ही, यहां के लोगों का भावपूर्ण और अतिथि सत्कार भी दुनिया भर के पर्यटकों को लुभा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए श्छत्तीसगढ़ होमस्टे नीत्यि तैयार

छत्तीसगढ़ अब अपनी माटी की खुशबू, समृद्ध जनजातीय परंपराओं और गांवों के नैसर्गिक सौंदर्य के दम पर देश–दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने को तैयार है। राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति (2024–2030) में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए श्छत्तीसगढ़ होमस्टे नीत्यि तैयार की है। इसी कड़ी में अब ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कारय्य की शुरुआत की गई है। इन तीनों निर्णयों से गांवों में रोजगार, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह त्रिआयामी मॉडल पर्यटन को स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा।

विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा

बारिश का मौसम बीतने के बाद से ही यहां हरे–भरे जंगल, पहाड़ और उनके उफनते पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में बस्तर भी देश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में एक साबित हो रहा है। हालांकि बस्तर का दशहरा बहुत पहले से प्रसिद्ध है, 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरा में कुछ खास होने वाला है, लेकिन हाल के दिनों में इस अवसर पर जुटने वाले सैलानियों की संख्या में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। इस वर्ष भी यहां का दशहरा देखने के लिए देश–विदेश से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नवरात्रि और दशहरा के अलावा यहां दीपावली पर भी दुनिया भर से भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं।

बस्तर के सहज जीवन से वैश्विक पहचान तक

बस्तर के बालक श्चेन्दरू मंडावीय्य की बाघ श्टेंबूय्य के साथ दोस्ती ने कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सहज ग्रामीण जीवन का डंका बजाया था।उसी नाम से राज्य सरकार ने श्चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कारय्य की शुरुआत की है। इसके लिए श्चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम 2025य्य लागू किया गया हैजो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी होगा। इस पुरस्कार के तहत ग्रामीण पर्यटन, लोककला, हस्तशिल्प और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण में लगे जमीनी नायकों या संस्थाओं को 1 लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय ज्यूरी इसका चयन करेगी और विजेता को राज्योत्सव के मंच पर सम्मानित कर उन पर एक सचित्र स्मारिका जारी की जाएगी।

बस्तर के श्टाइगर बॉयश के नाम से मशहूर चेन्दरू मंडावी की स्मृति में ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्चेन्दरूश राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यह पुरस्कार बस्तर के श्टाइगर बॉयश के नाम से मशहूर चेन्दरू मंडावी की स्मृति में शुरू किया गया है, जिन्होंने स्वीडिश फिल्म श्जंगल सागाश से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। गांवों की संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवनशैली को पर्यटन से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना। श्चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कारय्य उन लोगों और संस्थाओं को पहचान देने का प्रयास है, जो जमीनी स्तर पर पर्यटन के माध्यम से अपने गांव और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं।

होमस्टे से पर्यटक गांव की जीवनशैली जानेंगे

पुरस्कार और प्रोत्साहन के साथ–साथ राज्य सरकार की होमस्टे नीति इस पूरे ढांचे को व्यावहारिक धरातल प्रदान कर रही है। अब पर्यटक महंगे होटलों की बजाय गांवों में पारंपरिक घरों का अनुभव कर सकेंगे। पर्यटक गांव के ही घरों में रुकेंगे। होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, लोककला, लोकसंस्कृति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर और समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ देश में ग्रामीण पर्यटन का एक विशिष्ट मॉडल बन सकता है। पर्यटकों को ग्रामीणों के घरों में ठहरने, उनका पारंपरिक भोजन करने, चारपाई का उपयोग करने, खेत–खलिहान घूमने और कुएं का पानी आदि देखने–अनुभव करने का अवसर मिलता है।

होमस्टे के जरिए पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

होमस्टे नीति 2025–30 के माध्यम से ग्रामीण, जनजातीय और पर्यटन क्षेत्रों के परिवारों को अपने घरों को पर्यटन सुविधा में बदलकर अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं, पर्यटकों को स्थानीय खान–पान, कला, परंपरा, जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा नए होमस्टे की स्थापना तथा मौजूदा मकानों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के साथ संचालकों को आतिथ्य, स्वच्छता और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है। इससे मिलने वाला पैसा सीधे ग्रामीण परिवार, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों की जेब में जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। इस नीति से बस्तर और सरगुजा के अंचलों से लेकर मैदानी गांवों तक, होमस्टे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर समृद्धि के नए द्वार खोले गए

छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर को विशेष रूप से शामिल किया गया है। पर्यटन परियोजनाओं को सामान्य उद्योगों की तरह ही न्यूनतम पूंजी निवेश पर विभिन्न प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन सरकार इन्हीं संभावनाओं को साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर समृद्धि के नए द्वार खोले गए हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, गांव से लेकर शहरों तक हर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र से नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर होंगे निर्मित

साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, आवासीय सुविधाओं तथा पर्यटक सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटकों के लिए बेहतर ठहराव, परिवहन तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाया जा सकता है। विष्णु देव साय ने कहा राज्य में लगातार इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई गई है, जो प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निवेश से पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

गांव का युवा अपने ही क्षेत्र में पर्यटन उद्यमी बन सकेंगे

राज्य सरकार की नई उद्योग नीति में पर्यटन को सेवा उद्योग का दर्जा देने का कदम भी पर्यटन को गति देगा। इसके

तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, इको–टूरिज्म और होमस्टे विकसित करने वाले युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को विशेष कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान और सिंगल–विंडो क्लीयरेंस का लाभ मिलेगा। इसके अलवा ग्रामीण युवाओं को आतिथ्य, टूर गाइडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है, ताकि गांव का युवा अपने ही क्षेत्र में श्पर्यटन उद्यमी बन सकें।

मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून रद्द, हाईकोर्ट ने 14 प्रतिशत कोटा बरकरार रखाय रुके पदों पर नियुक्तिके निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले वर्ष 2019 के कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने नौ अक्टूबर 2026 को सुनाए गए फैसले में कहा कि राज्य सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए आवश्यक असाधारण परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सकी। इस फैसले के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत रहेगा। अदालत ने लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े पदों को भरने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी नियुक्तियां आरक्षण विवाद के कारण अटकी हुई थीं।

यह मामला मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार के उस फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत मार्च 2019 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया गया था। बाद में इसे कानून का रूप दिया गया। इससे पहले राज्य में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया, जिसके बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के बंटवारे को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गया। इस फैसले को कई याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामला वर्षों तक अदालत में लंबित रहा और विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में बढ़े हुए आरक्षण के प्रभाव को लेकर अनिश्चितता बनी रही।

हाईकोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या राज्य सरकार के पास ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और संवैधानिक आधार था। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाद ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिए जाने के अधिकार को लेकर नहीं, बल्कि आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को उचित ठहराने से संबंधित है। पीठ के अनुसार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना संवैधानिक उद्देश्य है, लेकिन आरक्षण की सीमा तय करने के लिए संबंधित वर्ग की स्थिति, सरकारी सेवाओं में उसके प्रतिनिधित्व और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों का ठोस आकलन आवश्यक है। अदालत ने आरक्षण की कुल सीमा से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों पर भी विचार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले में सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत रखने का सिद्धांत स्थापित किया था। इस सीमा से आगे जाने के लिए असाधारण परिस्थितियों और पर्याप्त औचित्य की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत करने के बाद राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण का कुल अनुपात 50 प्रतिशत से काफी ऊपर चला गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे असाधारण आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिनसे इस बढ़ोतरी को संवैधानिक रूप से उचित ठहराया जा सके।

फैसले में ओबीसी समुदाय के शैक्षणिक और सरकारी रोजगार में प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया। अदालत ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के वर्ष 2023 के अध्ययन, उच्च शिक्षा से संबंधित अखिल भारतीय सर्वेक्षण और सरकारी रोजगार के आंकड़ों पर विचार किया। फैसले में उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, उच्च शिक्षा में ओबीसी विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 33.87 प्रतिशत थी। वहीं, सरकारी पदों में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 28.16 प्रतिशत बताई गई। अदालत ने इन आंकड़ों को मौजूदा 14 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में देखते हुए कहा कि राज्य में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की स्थिति का आकलन किए बिना आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।

पीठ ने यह भी कहा कि केवल किसी समुदाय की जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाकर आरक्षण की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके लिए सामाजिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति से जुड़े प्रमाणों की आवश्यकता होती है। अदालत ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में लगातार कई मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से रहे हैं और मंत्रियों तथा विधायकों में भी इस वर्ग की पर्याप्त उपस्थिति रही है। हालांकि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने आप में सामाजिक या आर्थिक पिछड़ेपन की अनुपस्थिति का निर्णायक प्रमाण नहीं है। अदालत ने इन तथ्यों को अन्य शैक्षणिक और रोजगार संबंधी आंकड़ों के साथ मिलाकर देखा। फैसले का एक बड़ा असर उन सरकारी पदों पर पड़ सकता है, जिन्हें बढ़े हुए आरक्षण और उसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण रोककर रखा गया था। अदालत ने भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया कि विवादित व्यवस्था के तहत लंबित रखे गए 13 प्रतिशत पदों को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से तीन महीने के भीतर भरा जाए। इस आदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य संबंधित भर्ती एजेंसियों को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से परिणाम और नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह निर्देश महत्वपूर्ण है, हालांकि प्रत्येक भर्ती पर इसका वास्तविक प्रभाव संबंधित नियमों और आदेश की शर्तों के अनुसार तय होगा।

दिल्ली में जलभराव बना मासूमों की मौत का कारण, दो बच्चों का खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से मौत

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जलभराव की समस्या एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। रोहिणी सेक्टर 39 और 41 के पास जमा पानी में डूबने से सात और आठ वर्ष के दो बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि इलाके के लोगों में शोक के साथ–साथ नाराजगी भी है। घटना ने जलभराव से निपटने की व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, जलभराव में दो बच्चों के डूबने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद तलाश और बचाव अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान पहले एक बच्चे का शव बरामद हुआ, जबकि दूसरा बच्चा लापता था। गोताखोरों ने काफी प्रयासों के बाद दूसरे बच्चे का शव भी पानी से बाहर निकाल लिया।

मौके पर पहुंची अमन विहार थाना पुलिस ने दोनों बच्चों के शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिए। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इलाके में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है।

उनका कहना है कि यहां पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और यह तीसरी या चौथी घटना बताई जा रही है। यह क्षेत्र आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। हादसे के बाद लोगों ने जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है।

एक स्थानीय महिला ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बीट कांस्टेबल को बच्चों के डूबने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों की तलाश शुरू की गई। गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शव निकाले गए। महिला के अनुसार, पानी की गहराई बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी यह हादसा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लापरवाही के कारण यहां वर्षों से पानी जमा है।

दो मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब क्षेत्र में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है, तो अब तक इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया। लोगों ने संबंधित विभागों से जलभराव दूर करने, स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

हादसे ने एक बार फिर यह चिंता बढ़ा दी है कि खुले और असुरक्षित जलभराव वाले स्थान बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस घटना के बाद क्या कदम उठाते हैं और इलाके के लोगों को इस समस्या से कब तक राहत मिलती है।

अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर कसा हिटलर वाला तंज कहा-प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ेगा इस्तीफा



एजेंसी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर के शासन से की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की आवाज दबाई जा रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर राजधानी में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

केजरीवाल ने दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी के हालात अघोषित आपातकाल से भी बदतर हैं। उनके मुताबिक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं, छात्रों और मुख्यमंत्रियों को अपराधियों की तरह हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब किसी शासक का अहंकार चरम पर पहुंच जाता है, तो उसके पतन का समय नजदीक आ जाता है। उन्होंने हिटलर का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जनता की आवाज दबाने की कोशिशों का अंत अच्छा नहीं होता।

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि कथित तानाशाही रवैये के कारण एक दिन उन्हें भी पद छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची में कथित श्वोट चोरीच्य के मुद्दे का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि सरकार इन मामलों को लेकर इतनी चिंतित क्यों है।

उन्होंने यह भी पूछा कि यदि सरकार की मंशा साफ है, तो राजधानी में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, जिसकी तुलना उन्होंने लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से की। केजरीवाल ने कहा कि लाठी और जेल के सहारे लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता। उनके ये बयान विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच आए हैं।

केजरीवाल के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल मिलकर राजधानी में कानून–व्यवस्था बिगाड़ने तथा अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ऐसी किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी।

इस राजनीतिक विवाद के बीच दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों, पुलिस की कार्रवाई और मतदाता सूची से जुड़े आरोपों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

जहां विपक्ष पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश बता रहा है, वहीं भाजपा इसे कानून–व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई के संदर्भ में देख रही है।

दोनों पक्षों के आरोपों और दावों के बीच मामले पर राजनीतिक टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है।

मणिपुर में नगा-कुकी झड़पों में नौ लोगों की मौत, कई घर और दुकानें फूंकी गईं

इंफाल। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। कामजोंग, कांगपोकपी और उखरुल जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान नगा और कुकी समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। हिंसा के दौरान कामजोंग जिले में कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने चासाद पुलिस थाने के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। वहीं, कुकी संगठनों ने कांगपोकपी जिले में बंद का आह्वान किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा की शुरुआत नगा बहुल कामजोंग जिले के कुकी बहुल चासाद गांव में 42 वर्षीय महिला की मौत के बाद हुई। शुक्रवार रात सशस्त्र समूहों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान महिला को गोली लग गई थी। बाद में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और हिंसा की घटनाएं सामने आने लगीं।

पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा बलों के जवान पुलिस थाने के पास बने अवैध बंकरों को हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां चला दीं।

इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

मुंबई। मुंबई पुलिस ने शनिवार को अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए अभिनेता इमरान खान समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन के समर्थन में किया गया था। प्रदर्शनकारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गावदेवी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 126(2), 189(2), 189(3) और 189(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये धाराएं आदेश की अवहेलना, गलत तरीके से रोकने और गैरकानूनी जमावड़े से संबंधित हैं। मामले में पुलिस की ओर से आगे की जांच की जा रही है।

हिरासत में लिए जाने के कुछ ही समय बाद इमरान खान ने सामाजिक माध्यम पर पुलिस वैन के भीतर से अपनी एक तस्वीर साझा की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, लगता है मैं लंबी सैर पर जा रहा हूं।

एक अन्य वीडियो में इमरान ने अपनी हिरासत को लेकर कहा कि उन्हें इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि पुलिस उन्हें वहां क्यों लेकर आई है। उनके मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उन्हें सड़क से उठाकर वैन में बैठने को कहा और रिहा करने से पहले करीब दो घंटे तक पुलिस वैन में घुमाया गया।

इमरान ने कहा कि वैन में बैठने से पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी कोई विशेष मांग नहीं है। वे मुंबई के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अभिनेता की साथी लेखा वाशिंगटन और उनकी बहन मैरी खान को भी अगस्त क्रांति मैदान से हिरासत में लिया गया था।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक, लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ाने पर होगा विचार



चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होगी। बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार इनमें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा बढ़ाने, स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरित करने और ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन से संबंधित योजना को मंजूरी देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता के लिए निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में एक लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय की शर्त को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं, सामाजिक विकास से जुड़े कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले परिवारों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये सालाना करने पर भी विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा, योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली राशि चुनने का विकल्प समाप्त करने और प्रत्येक तीन महीने में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद योजना के पात्रता नियमों में बदलाव हो सकता है। बैठक में हरियाणा विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता और धनराशि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इन फैसलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं को गति देना है।

कैबिनेट की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ के सेक्टर–7 स्थित सरकारी आवास पर लगाए गए 27.17 लाख रुपये के दंडात्मक किराये को माफ करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।

अलीगढ़वा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त भारत-नेपाल सीमा पर डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा

सिद्धार्थनगर। भारत–नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा थानाक्षेत्र कपिलवस्तु, अलीगढ़वा में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल गस्तभ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा । जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया । भ्रमण के दौरान सीमा पर तैनात एसएसबी, पुलिस एवं सशस्त्र बलों के जवानों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने, अवैध आवागमन, तस्करी एवं घुसपैठ पर कड़ी नजर रखने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। सीमा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी, बैरियर एवं चेकिंग प्वाइंट का निरीक्षण कर सुरक्षा को और सुदृढ़ करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर निखिल चक्रवर्ती तथा थानाध्यक्ष कपिलवस्तु व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे ।



कपिलवस्तु थाने में आयोजित हुआ समाधान दिवस

सिद्धार्थनगर। शासन के मंशा के अनुरूप प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को सम्पूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। आज थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक महाजन की उपस्थिति में थाना कपिलवस्तु में थाना समाधान दिवस का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सम्पूर्ण थाना समाधान दिवस के अवसर पर आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा सुना गया। जिलाधिकारी ने समस्त राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिया कि भूमि विवाद, वरासत, बंटवारा आदि के जो प्रकरण हैं उनका मौके पर जाकर सही ढंग से निस्तारण करायें। किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर नाली का विवाद, चकमार्ग का विवाद व जमीन बटवारा व अवैध कब्जाध्पट्टा प्रकरणो को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के साथ मौके पर जाये। अधिकतम प्रकरणो को निस्तारण करायें, प्रकरण लम्बित कदापि न रखा जाये। जिलाधिकारी ने थाना समाधान दिवस में आये सभी शिकायतकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आपस में मिलकर रहे। किसी प्रकार का लड़ाई–झगड़ा न करे। जो भी प्रकरण आये है उसका निस्तारण मौके पर जाकर राजस्व के अधिकारीध्कर्मचारी करायेंगे। इस दौरान उपजिलाधिकारी नौगढ़ निखिल चक्रवर्ती, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु, राजस्व निरीक्षक व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



भाजपा कार्यालय सिद्धार्थनगर में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

सिद्धार्थनगर। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय सिद्धार्थनगर में शिक्षक एमएलसी चुनाव 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य ने की, जबकि संचालन चुनाव संयोजक अजय उपाध्याय ने किया। बैठक में क्षेत्र की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र पांडेय एवं क्षेत्रीय मंत्री कन्हैया पासवान उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, संगठनात्मक व्यवस्थाओं को मजबूत करने तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन के लिए विधानसभा प्रभारियों एवं विधानसभा संयोजकों के नाम तय किए गए। इसके साथ ही विधानसभा संचालन समितियों के गठन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। मतदान के दिन मतदान स्थलों पर एजेंट एवं सह–प्रभारियों के रूप में जिम्मेदारी निभाने वाले कार्यकर्ताओं के नाम भी निर्धारित किए गए, ताकि चुनाव के दौरान संगठनात्मक समन्वय एवं व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जा सके। बैठक में आगामी 12 अक्टूबर को गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री जी के विशाल जनसभा की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।



इस अवसर पर बैठक के सह–संयोजक मनोज कुमार मौर्य एवं दीपेंद्र चंद चौधरी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त श्रीमती साधना चौधरी, जिला महामंत्री पवन कुमार मिश्रा, फतेह बहादुर सिंह, फूलचंद जायसवाल, दिलीप चतुर्वेदी, विजयकांत चतुर्वेदी, दशरथ चौधरी केशवान राय, बजरंगी वर्मा,सच्चिदानंद चौबे, सुरेंद्र पांडे, सिद्धार्थ पाठक,रामनारायण, सिद्धार्थ चौधरी, मधुसूदन अग्रहरि सहित सभी मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कपियां मिश्र में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित,



सिद्धार्थनगर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कपियां मिश्र में बाल विकास परियोजना, सिद्धार्थनगर के तत्वावधान में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदंबिका पाल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक श्याम धनी राही उपस्थित रहे। इस अवसर पर आंगनवाड़ी बहनों के साथ संवाद, उपहार वितरण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी बहनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदंबिका पाल ने कहा आंगनवाड़ी बहने समाज में मातृशक्ति और बच्चों की सेवा के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करती हैं।

उनके समर्पण और मेहनत से बच्चों के पोषण, प्रारंभिक देखभाल तथा महिलाओं में जागरूकता लाने जैसे कार्यों को मजबूती मिलती है। सांसद ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आंगनवाड़ी बहनों की हमेशा चिंता की है तथा मानदेय बढ़ाने का कार्य भी किया है उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन एक माह तक सेवा समर्पण के रूप में मनाने का संकल्प लिया जिसके अंतर्गत रोज कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे है जिससे जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों को उपहार स्वरूप साड़ियों का वितरण किया। विशिष्ट अतिथि सदर विधायक श्याम धनी राही ने अपने संबोधन में कहा कि आंगनवाड़ी बहने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर जिला परियोजना निदेशक , उपायुक्त मनरेगा संदीप पाठक, परियोजना अधिकारी अनिल कुमार, साधना चौधरी, रमेश मणि, गंगा मिश्र, उद्योग विभाग से तौसलेन्द्र मिश्रा, सबलू सहानी, संजय कुमार, प्रमोद यादव सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नीरजा देवभूमि चौरिटेबल ट्रस्ट को विधिक सेवा एवं जागरूकता में योगदान के लिए सम्मान

देहरादून/ऋषिकेश। समाज के जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता और विधिक जागरूकता पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर में महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिए नीरजा देवभूमि चौरिटेबल ट्रस्ट, ऋषिकेश को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की ओर से प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान ट्रस्ट की संस्थापक डॉ. नीरजा गोयल को सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। ट्रस्ट को यह प्रमाण–पत्र शिविर के सफल आयोजन में सहयोग और सहभागिता के लिए दिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सम्मान प्रदान करने के अवसर पर सिविल जजध्न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऋषिकेश तथा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, ऋषिकेश की सचिव तान्या मिधा की भूमिका रही। प्रमाण–पत्र में न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल सहित संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है।

कानूनी जागरूकता से जरूरतमंदों को मिल सकती है राहत

कानून की जानकारी का अभाव अक्सर जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता से दूर कर देता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विधिक जागरूकता शिविर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों, कानूनी प्रक्रियाओं और सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध विकल्पों की जानकारी मिल सकती है।

इस दिशा में सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। सरकारी विधिक सेवा संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय से जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, ऐसे शिविरों की वास्तविक सफलता का आकलन केवल आयोजन या सम्मान के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए।

समय मंत्र
हिन्दी मासिक समाचार पत्र

हिन्दी मासिक समाचार पत्र समय मंत्र स्वामी,प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक प्रदीप कुमार द्वारा शिवम प्रेस ग्राम–पिपरा पाण्डेय पो0–धेन्सा नानकार जनपद सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश पिन कोड 272207 से मुद्रित कराकर ग्राम–पिपरा पाण्डेय पो0–धेन्सा नानकार जनपद सिद्धार्थनगर उ0प्र0 से प्रकाशित ।

सम्पादक

प्रदीप कुमार

मो0–9936720490

Email
samaymantra55@gmail.com

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र सिद्धार्थ नगर मान्य होगा।